भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1671
दिनांक 09 मई, 2016 को उत्तर देने के लिए

अवसंरचना और सम्पर्क का विकास

1671. श्री के. सी. त्यागी:
श्रीमती रजनी पाटिल:
श्री रामदास अठावले:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए अवसंरचना और सम्पर्क का विकास एक मात्र अति महत्वपूर्ण कारक है;
(ख) क्या सरकार ने अवसंरचना और सम्पर्क के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोई विशिष्ट गरीबी-रोधी कार्यक्रम बनाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – योजना मंत्रालय
तथा रक्षा राज्य मंत्री
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसकी शुरुआत दिसम्बर, 2000 में भारत सरकार के एक विशेष अंतःक्षेप के तौर पर की गई थी जिसका उद्देश्य संधारणीय गरीबी उपशमन सुनिश्चित करना था। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य प्रत्येक पात्र बस्ती तक स्तरीय और बारहमासी सड़के उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम शुरू होने से लेकर मार्च,2016 तक देश की कुल 1,16,310 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है जबकि लक्ष्य 1,78,000 बस्तियों का था और 4,72,627 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में "विशेष संवर्धित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)" नाम से एक महासड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दायरे को सितम्बर, 2005 से समय-समय पर बढ़ाया गया है। अब तक सरकार ने चरण-क के तहत 6418 किलोमीटर सड़कों को 2/4 लेन का बनाने की तथा पूरे पूर्वोत्तर में एसएआरडीपी-एनई के अरूणाचल पैकेज की मंज़ूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 33,750 करोड़ रूपए है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को 2020 तक ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। रेल सम्पर्क का गरीबी उपशमन पर प्रभाव पड़ता है। इससे आवश्यक वस्तुओं और ख़ासकर अनाज़ की कीमतें कम होंगी।

फरवरी, 2009 के दौरान सरकार ने वामपंथी उग्रवादपीड़ित (एलडब्ल्यूई) इलाक़ों में सड़कों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है जिसमें देश के 8 राज्यों जैसे-आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तरप्रदेश के 34 से ज़्यादा ज़िलों की जनजातीय उप-योजनाएं भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत 7300 करोड़ रूपए की लागत से 2 लेन स्टैंडर्ड वाली 5,477 किलोमीटर सड़कों (1,126 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 4351 किलोमीटर राज्य सड़कों) के विकास का लक्ष्य है। वर्ष 2016-17 के लिए 700 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

*****